राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

इंफोमेटिक्स

वॉल्यूम 30, सं 1, जुलाई, 2022

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से बच्चों के लिए पीएम–केयर्स योजना के तहत लाभ जारी किए

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत लाभ जारी करते हुए

एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से पीएम केयर्स इवेंट से जुड़े गणमान्य व्यक्ति

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2022 को एनआईसी की वीडियो कॉन्फ्रेंस सेवा के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी किए। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के साथ, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री इस आयोजन से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे।

कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्ति कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र/ स्नेह पत्र; माननीय प्रधानमंत्री का एक पत्र; पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम खाते की पासबुक; तथा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बच्चों को सौंपे गए।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी में अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को खोने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान कर उन्हें शिक्षा और छात्रवृत्ति के माध्यम से सशक्त बनाकर व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उन्हें 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना एवं स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करना।

यह योजना एक वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से परिचालित की जा रही है जिसे https://pmcaresforchildren.in पर देखा जा सकता है। पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है जो शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रचारित अन्य योजनाओं के साथ-साथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत कवर किए गए बच्चों को पंजीकरण, अनुमोदन और अन्य सभी सहायता/ लाभ प्रदान करने से संबंधित प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाता है।

पोर्टल को डिजाइन करने में कठिन समयसीमा को पूरा करने में एनआईसी के अथक प्रयास और आयोजन के सुचारू संचालन में इसके अथक समर्थन की सभी हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों द्वारा सराहना की गई। उपयोगकर्ता विभाग ने बच्चों के पंजीकरण से लेकर पात्र बच्चों को लाभ के हस्तांतरण तक की पूरी प्रक्रिया में एनआईसी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

– सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम–किसान योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, 10.12 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को पीएम-किसान योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपये जारी करते हुए

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2022 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 10.12 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय लाभ राशि जारी की।

श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री जयराम ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार के साथ कार्यक्रम में राज्य के कई अन्य मंत्री मौजूद थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और किसान एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

कार्यक्रम के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अन्य विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों के साथ बातचीत की ताकि उनके जीवन पर केंद्रीय कल्याण योजनाओं के प्रभाव को जाना जा सके।

पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल एनआईसी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे लाभ हस्तांतरित करने के लिए एक एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है। क्वाड्रिमेस्टर अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान, अधिकांश लाभार्थियों (लगभग 8.75 करोड़) ने आधार आधारित भुगतान मोड का उपयोग करके भुगतान प्राप्त किया है। इस अवधि में पीएम-किसान पोर्टल में कई नई सुविधाओं जैसे एनटीआरपी एकीकरण के माध्यम से धनवापसी तंत्र, ऑनलाइन ओटीपी-आधारित के साथ-साथ बायोमेट्रिक-आधारित केवाईसी सुविधा के साथ-साथ आयकर जैसी बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकरण और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए पेशनभोगियों का डेटाबेस को शामिल किया गया है। इस प्रणाली को राज्य की भूमि अभिलेख प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, वन नेशन वन राशन कार्ड डेटाबेस के साथ एकीकरण प्रगति पर है। इसके अलावा, कई अन्य सुविधाओं को भी उन्नत सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है जैसे कि लाभार्थियों की स्थिति को जानें, आयकर दाता की पहचान, सीएससी एकीकरण, ऑनलाइन स्वयं पंजीकरण और यूआईडीएआई के साथ जुड़ाव, खाता सत्यापन और भुगतान फाइलों के समाधान के लिए पीएफएमएस ऐक-नैक सुविधाएँ, अनन्य किसान सूची का थोक प्रसंस्करण और फिर आरएफटी हस्ताक्षर और एफटीओ निर्माण के लिए सूची किश्तों का वितरण, भौतिक सत्यापन का यादृच्छिक चयन, सुरक्षित लॉगिन के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण, आदि।

– अजय सिंह चहल, हिमाचल प्रदेश

रेलटेल, एनआईसी और निकसी ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (रेलटेल), रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी); और नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड (निकसी), एनआईसी के तहत भारत सरकार के एक उद्यम ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है, जिसका उद्देश्य ''एक दूसरे के साथ सुविधाओं और क्षमताओं का लाभ उठाकर और तालमेल करके उपयोगकर्ता संगठनों को वन-स्टॉप प्रबंधित एंड-टू-एंड एनआईसी ई-ऑफिस और स्पैरो समाधान प्रदान करना है।''

डॉ राजेंद्र कुमार, अपर सचिव, एमईआईटीवाई, भारत सरकार, श्री पुनीत चावला, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रेलटेल, श्री संजय कुमार, निदेशक (नेटवर्क योजना और प्रबंधन), रेलटेल, श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक (वित्त), रेलटेल, श्रीमती रचना श्रीवास्तव - उप महानिदेशक, एनआईसी, और श्री प्रशांत कुमार मित्तल - प्रबंध निदेशक, निकसी, एमओयू हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर उपस्थित थे।

रेलटेल ने हाल ही में अपने 216 प्रतिष्ठानों (जोनों/ मंडलों/ सीटीआइ/ कार्यशालाओं) पर भारतीय रेलवे के लिए एक मेगा ई-ऑफिस परियोजना लागू की है। ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर भारतीय रेलवे के 1.38 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जो 20 लाख से अधिक ई-फाइलों को संभालते हैं और 1.36 करोड़ से अधिक ई-रसीदें उत्पन्न करते हैं। यह देश में सबसे बड़े एनआईसी ई-ऑफिस रोल-आउट में से एक है। ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से बढ़ी हुई पारदर्शिता, फाइलों का त्वरित और व्यवस्थित निपटान, और कागज रहित कार्यालय पद्धति को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंट में कमी के साथ-साथ लंबित फाइलों की समय पर निगरानी हुई है।

इस अवसर पर, श्री राजेंद्र कुमार, अपर सचिव, एमईआईटीवाई ने बताया कि ई-ऑफिस का उपयोग सरकारी विभागों द्वारा राज्य और केंद्र दोनों स्तरों के साथ-साथ देश भर के सार्वजनिक उपक्रमों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस हाल ही में कोविड-19 के दौर में सरकारी कार्यालयों को क्रियाशील रखने में जीवन रेखा साबित हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे इस समझौता ज्ञापन के बाद, निकसी, और एनआईसी रेलटेल प्रबंधित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करते हुए अन्य एनआईसी/निकसी

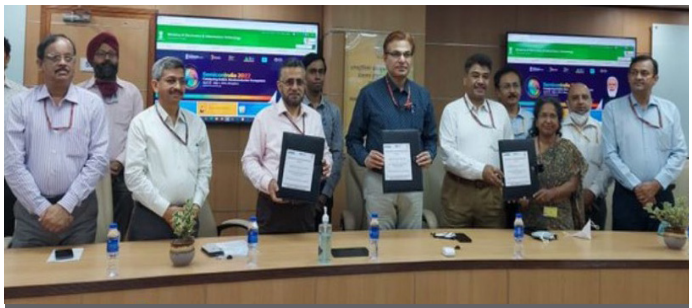

रेलटेल, एनआईसी और निकसी ने डॉ राजेंद्र कुमार, अपर सचिव, एमईआईटीवाई, भारत सरकार की उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सॉफ्टवेयर उत्पादों की पेशकश के लिए सहयोग का लाभ उठा सकते हैं।

श्रीमती रचना श्रीवास्तव, डीडीजी और एचओजी, एनआईसी ने बताया कि देश में अकेले ईफाइल मॉड्यूल का उपयोग 8.77 लाख से अधिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और अब तक 3.19 करोड़ से अधिक फाइलें बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली स्थानीय भाषाओं के लिए सक्षम है और कई राज्य अपनी-अपनी भाषाओं में ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।

– सूचना-विज्ञान समाचार डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा राष्ट्रीय ई–विधान एप्लिकेशन सेवा केंद्र एवं टेबलेट से लैस विधान मंडप का उद्घाटन

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार, 19 मई 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना की उपस्थिति में एनईवीए (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन) सेवा केंद्र और टैबलेट से लैस उत्तर प्रदेश विधान मंडप का उद्घाटन किया।

उत्तर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय राज्य वित्त और संसदीय कार्य मंत्री, श्री दयाशंकर सिंह, माननीय राज्य परिवहन मंत्री, श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव (गृह), श्री प्रदीप दुबे, प्रमुख सचिव, इस अवसर पर विधानसभा में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन एक उपकरण-तटस्थ एप्लिकेशन है जो विधान सभा के सदस्यों को सदस्य संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित/ अतारांकित प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर प्रस्तुत करना, प्रस्तुत किए गए कागजातों, समिति की रिपोर्टों आदि को उपकरण / टैबलेट और स्मार्ट तरीके से विविध हाउस बिजनेस को कुशलता से संभालने के लिए सभी विधायिकाओं / विभागों की पूरी जानकारी से सुसज्जित किया गया है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन डेटा के संग्रह के लिए नोटिस / अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। क्लाउड प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तैनात डेटा को किसी भी समय कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन को 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में लागू किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से विधानसभा को कागज रहित बनाया जाना चाहिए और यूपी विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों और संबंधित अधिकारियों को इस परियोजना को सफल बनाना होगा।

इस परियोजना के तहत, राज्य विधानमंडल के सभी सदस्यों, राज्य विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और राज्य के सरकारी विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के विभिन्न मॉड्यूल पर अभिविन्यास / प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन सेवा केंद्र और टैबलेट से लैस विधान मंडप का उद्घाटन करते हुए

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन सेवा केंद्र में सभी आधुनिक कंप्यूटर आधारित शिक्षण सहायक सामग्री के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। ई-विधान एमएमपी पर प्रशिक्षण के लिए एमओपीए द्वारा ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी विकसित की जाती है।

– राजीव रस्तोगी, उत्तर प्रदेश

चंडीगढ़ के माननीय प्रशासक एनआईसी यूटी चंडीगढ़ द्वारा विकसित 86 ई– सेवाओं का शुभारंभ किया

पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारीलाल पुरोहित ने 2 मई 2022 को नागरिकों के लाभ के लिए केंद्र सरकार के ई-गवर्नेंस मिशन के तहत एनआईसी चंडीगढ़ यूनिट द्वारा विकसित और डिजाइन की गई 86 ई-सेवाओं का शुभारंभ किया

ई-सेवाओं को डिजाइन और विकसित करने में एनआईसी चंडीगढ़ यूनिट द्वारा किए गए विपुल कार्य की माननीय राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित ने प्रशंसा की। माननीय संसद सदस्य, चंडीगढ़, श्रीमती किरण खेर और प्रशासक के सलाहकार श्री धर्म पाल ने भी एनआईसी चंडीगढ़ यूनिट द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई 86 ई-सेवाओं के विवरण को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय संपत्ति से संबंधित योजनाओं को कवर करते हुए 8 ई-सेवाएं शुरू कीं।

(ii) चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड (सीएलडब्ल्यूबी) और चंडीगढ़ बिल्डिंग एंड अन्य निर्माण कार्यकर्ता वेलफेयर बोर्ड (सीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड) ने 24 योजनाओं को शामिल करते हुए 5 सेवाएं शुरू कीं।

(iii) आबकारी और कराधान विभाग, चंडीगढ़ ने 86 नियामक अनुपालन प्रमाणपत्रों को कवर करते हुए 23 सेवाओं को ऑनलाइन किया।

(iv) 27 प्रत्यक्ष लाभ योजनाएँ ऑनलाइन की गईं।

(v) परिवहन विभाग, चंडीगढ़ ने 17 सेवाओं को ऑनलाइन किया।

(vi) संपदा कार्यालय, चंडीगढ़ ने 5 सेवाओं को ऑनलाइन किया।

ई-गवर्नेंस सरकार को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाती है और संदेह या गलत बयानी के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। ई-सेवाओं से न केवल चंडीगढ़ के लोगों को बल्कि चंडीगढ़ के आसपास के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी पूरी प्रक्रिया को गैर-बोझिल बनाने का लाभ मिलेगा। आम जनता सेवाओं का लाभ उठा सकती है और संबंधित कार्यालयों में आए बिना और अपने खाली समय में अपना काम करवा सकती है। इन सेवाओं का लाभ वेब के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी उठाया जा सकता है। सेवाएं फेसलेस / कॉन्टैक्टलेस होंगी और संबंधित विभागों में आगंतुकों के आने-जाने में कमी आएगी।

– मनराज कौर, चंडीगढ़

माननीय मुख्यमंत्री गुजरात ने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना का शुभारंभ किया

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने 1 मई 2022 को 53 वें गुजरात फाउंडेशन दिवस के अवसर पर पाटन जिले में अन्य विकास परियोजनाओं के साथ सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेशण करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा विधियों को तैयार करने के लिए केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस सिस्टम आई आर ए डी (एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस) लॉन्च किया।

समारोह में माननीय मंत्री श्री जगदीश ईश्वरभाई विश्वकर्मा और माननीय मंत्री श्री जीतू वघानी भी शामिल हुए। श्री आशीष भाटिया, डीजीपी गुजरात, श्री पीके सिंह, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, श्री एचपी मेहता, तकनीकी निदेशक और राज्य समन्वयक एनआईसी गुजरात, श्री अजय सिंह जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी सहित सभी हितधारक विभागों के (पुलिस, परिवहन, सड़क और भवन, स्वास्थ्य) के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

आई आर ए डी परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ), भारत सरकार की एक पहल है, और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। एनआईसी, गुजरात ने राज्य और जिला दोनों स्तरों पर रोलआउट प्रबंधकों को तैनात किया है। टीम ने 440 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें सभी चार हितधारक विभागों के लगभग 7500 अधिकारियों ने भाग लिया। परियोजना को गति देने और स्थानीय स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित बैठकें भी आयोजित की गईं।

– अमित दिनकरभाई शाह, गुजरात

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेंद्रभाई पटेल, गुजरात में केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रणाली आई आर ए डी का शुभारंभ करते हुए

एनआईसी असम ने असम सीएम ब्रेन चाइल्ड – सीएम–ट्रांस लागू किया

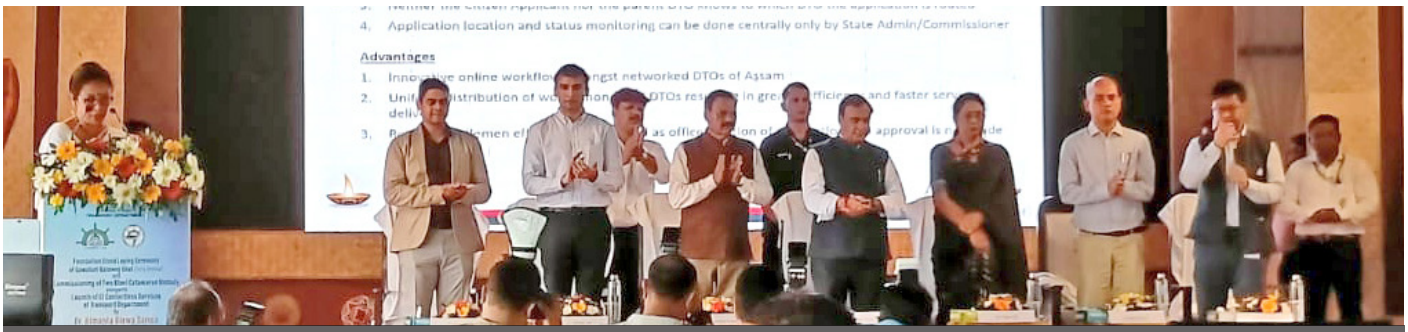

असम के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा, सीएम-ट्रांस पोर्टल लॉन्च करते हुए

सीएम-ट्रांसपोर्ट रैंडमाइज्ड एलोकेषन नेटवर्क सिस्टम (सीएम-ट्रांस) को असम के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 13 मई 2022 को शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के तट पर लॉन्च किया गया था।

सीएम-ट्रांस एक क्रांतिकारी ऑनलाइन कार्य आवंटन प्रणाली है जो परिवहन कार्यालयों के बीच समान रूप से काम वितरित करेगी, दक्षता में सुधार करेगी, सेवा वितरण में तेजी लाएगी, बिचौलियों के हस्तक्षेप और भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करेगी।

उपन्यास प्रणाली की अवधारणा असम के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने स्वयं की थी और इसे एनआईसी असम द्वारा असम परिवहन विभाग में लागू किया गया है।

असम यादृच्छिक कार्य आवंटन प्रणाली को अपनाने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। सीएम-ट्रांस उन सभी संपर्क रहित परिवहन सेवाओं पर लागू होता है जो वर्तमान में असम के नागरिकों को दी जा रही हैं और धीरे-धीरे अन्य सभी ऑनलाइन परिवहन सेवाओं तक विस्तारित की जाएंगी।

नई प्रणाली जिला परिवहन कार्यालयों (डीटीओ) में सेवाओं के लिए आवेदनों के सत्यापन और अनुमोदन की अवधारणा को दूर करती है जिसमें उन्हें जमा किया जाता है और इसके बजाय उन्हें अपने व्यक्तिगत कार्यभार के आधार पर असम के 32 डीटीओ में से किसी में यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। कम काम के साथ आवेदन स्वतः ही डीटीओ के पास पहुंच जाते हैं। कार्य का यह समान वितरण अधिक दक्षता और तेज सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। आवेदकों और डीटीओ को सूचित नहीं किया जाता है कि आवेदनों को यादृच्छिक रूप से कहां भेजा गया है। यह बिचौलियों की भूमिका का पूर्ण उन्मूलन और आवेदकों के अनावश्यक उत्पीड़न को सुनिश्चित करता है।

सीएम-ट्रांस का शुभारंभ करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री ने न केवल परिवहन क्षेत्र में बल्कि राज्य के राजस्व क्षेत्र में भी एनआईसी असम राज्य इकाई द्वारा किए गए असाधारण कार्यों की सराहना की। उन्होंने इसी कार्यक्रम में 12 और वाहन तथा सारथी संपर्क रहित सेवाएं भी शुरू कीं। असम में संपर्क रहित सेवाओं की कुल संख्या 25 हो गई है।

– कविता बरकाकोटी, असम

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे में नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिए News पर जायें https://informatics.nic.in/news